ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा में सेवाओं के सरलीकरण पर ज़ोर

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में तेजी और निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनने के उद्देश्य से सभी विभाग करे कार्य: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह

निवेशकों की सुविधा के लिए फॉर्म होंगे सरल और द्विभाषी: मुख्य सचिव

लखनऊ, 30 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश में व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को और अधिक सरल एवं निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन लोक भवन, लखनऊ में मुख्य सचिव **श्री मनोज कुमार सिंह** की अध्यक्षता में किया गया।

इस बैठक में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की भागीदारी रही, जिसका नेतृत्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव **श्रीमती मीता राजीवलोचन** ने किया। उनके साथ कैबिनेट सचिवालय के अपर सचिव श्री राहुल शर्मा, डीपीआईआईटी और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान श्रीमती मीता राजीवलोचन ने प्रमुख सुझाव साझा किए, जिनमें डीआईवाई (Do-It-Yourself) वीडियो गाइड्स तैयार करना, विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, एक प्रतिक्रियाशील कॉल सेंटर की स्थापना और समस्याओं की ट्रैकिंग के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना शामिल था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि **अनापत्ति प्रमाणपत्र (NoC) और अन्य स्वीकृतियों से संबंधित फॉर्म** को अत्यंत सरल और आम व्यक्ति की समझ में आने योग्य बनाया जाए।

इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री शशांक चौधरी ने विभागवार 23 प्राथमिक क्षेत्रों और 71 उप-प्राथमिक क्षेत्रों की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इसमें आवास एवं शहरी नियोजन, श्रम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपीपीसीएल, अग्निशमन विभाग, राजस्व परिषद और इन्वेस्ट यूपी जैसे प्रमुख विभागों को शामिल किया गया है। यह योजना प्रदेश सरकार की व्यापार-अनुकूल वातावरण सृजन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने विभागीय फॉर्मों को अधिक सरल और द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) स्वरूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे निवेशकों को प्रक्रिया समझने में आसानी होगी और राज्य में निवेश के अनुभव को बेहतर किया जा सकेगा।